

संपादकीय

उर्जित आर्थिकी के प्रश्न

देश को हकीकत जानने का हक

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ऐसे समय में संसद की स्टॉडिंग कमेटी के समक्ष पेश हुए जब केंद्रीय बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बीच कई मुद्दों को लेकर गहरे मतभेदों की खबरें छन-छन कर बाहर आती रही हैं। सवाल केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता का भी उठा और आरबीआई के आरक्षित कोष में सरकार के दावे को लेकर भी। जिन संवेदनशील मुद्दों पर स्थायी समिति स्पष्टीकरण याह रही थी, उनमें आरबीआई में सुधार, सरकार के साथ तानाव, नोटबंदी व एनपीए से जुड़े सवाल, अर्थव्यवस्था से जुड़े हालात व चुनौतियां समिल थीं। हालांकि, गवर्नर उर्जित पटेल ने संवेदनशील मुद्दों पर विवाद को टालने के लिये बेहद नपे-तुले शब्दों में फूक-फूक कर जवाब दिये। वहीं नोटबंदी को लेकर उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, वह अस्थायी था। यद्यपि उन्होंने किसी भी क्षेत्र के लिये डैट मानदंडों में राहत देने की बात नहीं मानी। सरकार के साथ आरबीआई के सेक्शन-7 पर विवाद के बारे में उर्जित पटेल ने कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद वे किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से बचे। वहीं गवर्नर ने आरबीआई की चुनौतियों व विवादास्पद मुद्दों पर अगले दस-पंद्रह दिनों में लिखित जवाब देने का आश्वासन संसदीय समिति को दिया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एम. वीरपा मोइनी की अध्यक्षता व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाली 31 सदस्यीय समिति के सामने उर्जित पटेल ने माना कि वैथिक स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरने का फायदा देश की अर्थव्यवस्था को द्दुआ है और इससे चालू खाते का घाटा कम होगा। हालांकि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि आरक्षित कोष के आकार तथा लघु एवं मझोले उद्यमों के लिये कर्ज नियमों में ढील के मुद्दे पर बैंक व केंद्र सरकार में तनातनी चल रही थी बल्कि डिटी गवर्नर विरल आर्चर्च ने तो यहां तक कह दिया कि जिन देशों में केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता कम की गई है, वहां अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा है। दूरअल, सरकार को यह अस्थायी था कि नोटबंदी से तीन-साढ़े तीन लाख करोड़ की मुद्रा चलन से बाहर हो जायेगी, जिसे बैंकिंग तरलता के लिये इस्तेमाल किया जा सकेगा। मगर 99 प्रतिशत कर्तेंशी की वापरी से यह अनुमान विफल साधित हुआ, जिसकी पूर्ति के लिये सरकार बैंक के आरक्षित कोष की नकदी चाह रही थी। बाजार में नकदी की मांग बढ़ने पर पूर्ति के लिये अब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत इस माह बैंकिंग सिस्टम में चालीस हजार करोड़ डालने जा रहा है।

इथोपिया में सैलरी न मिलने से नाराज स्टाफ ने आईएलएण्डएफएस के भारतीय कर्मचारियों को बनाया बंधक

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्तीय संकट का सामना कर रही इफ्नास्ट्रक्टर लीजिंग एंड फाइनैशल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएण्डएफएस) के 7 भारतीय कर्मचारियों को आप्नी कंपनी देश इथोपिया में लोकल स्टाफ ने बंधक बना लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय बंधक बनाए गए कर्मचारियों के दावों की जांच कर रहा है। इन कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी के 12.6 अब डॉलर के लोन डिफॉल्ट के बाद लोकल स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है, जिसके बाद उन्होंने इहाँ बंधक बना लिया है। 7 भारतीय कर्मचारियों को इथोपिया की 3 अलग-अलग जगहों पर 25 नवंबर से ही



भेजे गए ई-मेल के मुताबिक इन्हें ओरेमिया और अहमरा स्टेट में बंधक बनाया गया है। बंधक बनाए गए कर्मचारियों का कहना है कि भारतीय और स्पेनिश कंपनी के जॉइंट वेंचर द्वारा बनाई जा रही कुछ सङ्करण परियोजनाओं पर काम रोके जाने के बाद शायद स्थानीय कर्मचारी दहशत में आ गए। इनका कहना है कि स्थानीय अधिकारी और पुलिस भी लोकल स्टाफ का ही पक्ष तेरे हैं। विदेश मंत्रालय और इथोपिया में भारतीय दूतावास के अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि मामले पर करीबी नजर रखी जा रही है। मामले का

समाधान निकालने के लिए इथोपिया के अधिकारियों और आईएलएण्डएफएस मैनेजमेंट के साथ वह संपर्क बनाया गया है। वहीं, नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने भी पूछी की है कि वे इस मामले को देख रहे हैं। आईएलएण्डएफएस के प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग के सवालों पर कोई भी टिप्पणी करने से इकाकर कर दिया है। वहीं, ओरेमिया के पुलिस कमिशनर जनरल अलेमैयेरु एजिंगु, डेयुटी स्पोकरपर्स डेरेसा ट्रेफ और अमहारा स्टेट के स्पोकरपर्स नियुसु तिलाहुन ने 2-2 फोन कॉल्स और 2-2 टेक्स्ट मेसेज का तुरंत जवाब नहीं दिया है।

अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा, कोयले से बिजली बनाना महंगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक

अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि

कोयले से बिजली बनाना अधिक

महंगा है। ऊर्जा के

नवीकरणीय स्रोत

भारत में नए कोयला

आधारित बिजली

संयंत्रों की तुलना में

बेहद कम लागत में

अधिक बिजली प्रदान कर सकते हैं

और इसका लाभ करदाताओं को

होगा। वित्तीय शिक्षिक टैक्स का

कार्बन ट्रैकर

द्वारा गत वर्षों में कोयले की विजली में

आधिक और वित्तीय जोखियों को पता

लगाना नामक अध्ययन में कहा गया है

कि कोयले की तुलने के बाद बिजली के

प्रयोग को समाप्त करने से

उपभोक्ताओं और करदाताओं को

फायदा होगा जबकि भारत एक

विनियमित बाजार है जहां राज्य का

आधारित करदाताओं को धीरे धीरे

समर्थन करने से अरबों रुपये बच

सकता है, लेकिन यह कोयले के

मालिकों के मुकाफ को प्रभावित

करेगा।

विनियमित बाजारों में निवेश जेखिम

को कम करता है, जहां कोयले को

प्रतिस्पृशजू से मुक्ति मिली हुई है।

चीन, भारत, जापान

और अमेरिका के कुछ

हिस्सों में आमतौर पर

उत्पादन लागत को

मंजूरी दे दी जाती है

और इसे उपभोक्ताओं

से बसूला जाता है।

इसमें कहा गया है कि लंबी अवधि

में कोयले का साप्तर्यन करने से

आधिक अप्रतिस्पृश और सावजनिक

वित्त को खतरा होगा, क्योंकि

राजनेताओं को कोयले की विजली को

सिस्टिक्सी देने की चाही राज्यों के

कोयले बढ़ी कीमतों के बीच चयन

करने के लिए मजबूर होता है।

अध्ययन के अनुसार कोयला

आधारित करदाताओं को धीरे धीरे

समर्थन करने से अरबों रुपये बच

सकता है, लेकिन यह कोयले के

मालिकों के मुकाफ को प्रभावित

करेगा।

इंग्लैंड के लिए खेल सकते हैं आर्चर

लंदन (आरएनएस)। जोफ्रा आर्चर अगले साल होने वाले

विश्व कप और एशेज सीरीज में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा अपने टीम में खेलने की योग्यता वाले नियम

में बदलाव करने के बाद मिल सकता है। वेबसाइट ईएसपीएन्क्रिक्ट एंड फोर्म ने बैठक में अपने रेजिवेंशनल नियम में बदलाव करना लिए छोला दी गई है, जो पहली तिमाही में 8.2 फीसदी रही थी। हालांकि एक साल पहले की इसी तिमाही में 8.2 फीसदी रही थी। हालांकि एक साल पहले की इसी तिमाही में यह अकड़ा 6.3 प्रतिशत था।

को साल इंग्लैंड में गुजराने होते थे जिसे बोर्ड ने कम कर तीन साल कर दिया है। आर्चर 2015 में इंग्लैंड आए थे और तब से वह इंग्लैंड की काउंटी सासेक्स से खेल रहे हैं। आर्चर मूलतः वेस्टइंडीज के बालांडोस से हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए अंडर-19 विश्व कप भी खेला है। ईसीबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है उन्से देश में बाहर से आए खिलाड़ियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। पहले इंग्लैंड की राशी टीम में खेलने के लिए खिलाड़ी

को साल इंग्लैंड में गुजराने होते थे जिसे बोर्ड ने कम कर तीन साल कर दिया है। आर्चर 2015 में इंग्लैंड